

एक नजर

मण्डलायुक्त ने दिलायी शपथ

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। मण्डलायुक्त वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयुक्त समारोह में भारत रत्न लोह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयन्ती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलायी गयी। उन्होंने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित किया।

इस अवसर पर अपर आयुक्त (न्यायिक) सुरेंद्र प्रसाद यादव, अपर आयुक्त (प्रशासन) मनोज कुमार तिवारी, संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी, उप निदेशक चंचायत, हरिहरेश बहादुर, उपप्रमुख श्रीमती रचना केशरवाणी, वैदिक सहायक बजरंग बली पाण्डेय, प्रशासनिक अधिकारी संतोष कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ सहायक जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शमीम अहमद, अमित उपाध्याय, शैलेश श्रीवास्तव, राजेश रसाल, अनुपम चौधरी, संदीप यादव, सौरभ कुमार, महेंद्र कुमार, आफताब अहमद, ओम प्रकाश चौधरी, सुहेल अहमद, पवन यादव, आलोक सिंह, शाल्मली शर्मा, संजय श्रीवास्तव, मुमताज अहमद सहित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। पड़रिया दत्तु खेल मैदान में सरदार बल्लभभाई पटेल की जयन्ती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। सरदार राम प्रसाद चौधरी और विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने प्रतिमा का अनावरण कर पुष्प अर्पित किए।

राष्ट्रीय विधानसभा क्षेत्र के दसिया-महडुआ मार्ग पर स्थित खेल मैदान में हुए कार्यक्रम का संयोजन राम प्रसाद चौधरी ने किया। इसमें जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिथियों ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान की याद दिलायी। उन्होंने कहा कि पटेल ने सैनिकी रियासतों का ऐक्यकरण कर अखंड भारत के निर्माण में भूमिका निभाई। मौजूद लोगों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बहादुर मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और अखंडता मजबूत करने का आह्वान किया गया।

मनीष मिश्रा ने सर पर जूता रखकर लिया संकल्प



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। भाजपा नेता मनीष मिश्रा ने तोफखाने में मिले जुते पैरों में पतखन के बजाये फिर पर शपथ लिए। उन्होंने इसे बस्ती के विकास का संकल्प बताया। मनीष मिश्रा का कहना है कि जब तक वह बस्ती में 500 से 1000 करोड़ रुपये का निवेश नहीं लायेंगे, तब तक जुते नहीं पहनेंगे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। पहले सोशल मीडिया पर एडुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक मनीष मिश्रा ने कहा कि बस्ती उनकी मातृभूमि है। यहां आने पर वह जुते उतारकर मोजे पहनेंगे। उन्होंने जोर दिए पर रखने को भी बस्ती के विकास के जुड़ा संकल्प बताया। मनीष मिश्रा के संस्थान के जरिए गरीब मरीजों के इलाज के लिए आर्थिक मदद, जरूरतमंदों को मुफ्त एंजलिया सुविधा, कैंसर पीड़ितों को मुफ्त एंजलिया सुविधा, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग किए जाने की बात कही जाती रही है।

चुनाव आयुक्त के खिलाफ जन महाभियोग: मॉक संसद में बोले राहुल—2024 का लोकसभा चुनाव अवैध



नई दिल्ली (आभा)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को अवैध बताया है। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे के आवास पर आयोजित मॉक पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि विश्व गठन पुरीकरण (एक्सट्राजुडर) के दौरान 13 करोड़ रुपये से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। राहुल ने पूछा चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को क्या कहेंगे, इन लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान किया था।

राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा

बच नहीं पाएंगे और उन्हें जनता को जवाब देना होगा।

राहुल गांधी ने कहा कि पिछले ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार एक व्यक्ति के रूप में अलग हैं और चुनाव आयोग जैसी संस्था के प्रमुख के तौर पर उनकी भूमिका अलग है। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका के साथ जो कुछ हो रहा है, उसे रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बना था। इसी वजह से विश्व को यह कठम

भाजपा नेता अभिषेक कुमार ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र: किसानों को फसलों का मुआवजा देने का आग्रह

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री एवं सांख्यिक के ब्लाक प्रमुख अभिषेक कुमार ने जैनपद में 30 एवं 31 अक्टूबर को आए अनिवार्यकत के प्रभाव से तैज आभी-तूफान और लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की धान की फसल को हलू नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे पत्र में प्रभावित किसानों की फसलों का तत्काल सर्वेक्षण करारकर सुगुंमि मुआवजा दिलाने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में भाजपा अभिषेक कुमार ने कहा कि जैनपद में कृषकता के प्रभाव से आई लेट आभी और लगातार बारिश के कारण किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई खेतों में खड़ी धान की फसल जलमग्न हो गई है तो कहीं तेज हवा और बारिश के कारण फसल जमीन पर गिर गई है। इससे किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है और उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। लोह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के 151 वीं जयन्ती पर शनिवार को सरदार पटेल स्मारक संस्थान परिसर में याद किया गया। सरदार राम प्रसाद चौधरी, वि.अरुण राजेंद्र चौधरी, कविन्द्र चौधरी, अतुल ने पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को नमन किया।

बाद छत्रपति साहू जी समारोह में आयोजित गोष्ठी मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुये माध्यमिक शिक्षा सेवा पवन बोर्ड के पूर्व सदस्य डा. दत्तरथ चौधरी ने कहा कि किसान के बेटे रूप में पटेल जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के वावजूद अपनी सुविधा की जगह देश के हितों को मिला दिया। उन्होंने 562 रियासतों को एकता के सूत्र में बांध कर भारत के स्वरूप को सशक्त बनाया। देश को आजाद कराने से लेकर गृह मंत्री के रूप में देश के निर्माण में

उत्ताना पड़ा। राहुल गांधी ने दावा किया कि एएसआईआर के तहत 13 करोड़ से ज्यादा (करीब 15 फीसदी) मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या देश के हर सात में से एक व्यक्ति के बराबर है। राहुल के मुताबिक, इन लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान किया था।

राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा

बस्ती के औषधि प्रयोगशाला में जांच शुरू

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। बस्ती मंडल के लोगों को खाद्य पदार्थों और दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए अब दूसरे जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की परिचयिका के तहत 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी औषधि खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में शनिवार से नमूनों की जांच होगी। अब तक खाद्य पदार्थों के 26 और दवाओं के 12 नमूने जांच के लिए मिले हैं।

शनिवार को धानिक अनुष्ठान और पुला-पाद के बाद सहायक आयुक्त (खाद्य), बस्ती मंडल ने फीता काटकर जांच का काम शुरू किया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच होगी। रोशन जैकब और बस्ती के मंडलायुक्त के प्रयासों से प्रयोगशाला शुरू हो सकी।

डीएम ने राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की दिलायी शपथ



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। लोह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयन्ती के अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती कल्याणी ज्योत्सना ने कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ दिलायी। उन्होंने सभी को शपथ दिलायी कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करेंगे और अपने देवतावासियों को बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करेंगी। उन्होंने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को देश की आंतरिक

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने की सलाह दी। इस अवसर पर आयुक्त (न्यायिक) राजेश चौधरी के साथ उनके चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एडीएम ज्ञान चन्द्र गुप्ता, सीआओ कीर्ति प्रकाश भारती, डीसी मननारा संजय शर्मा, उप जिला अधिकारी उमकांत तिवारी, राजेश यादव, रमेश यादव, कलेक्ट्रेट के वीरेंद्र कुमार, प्रेम प्रकाश, सुरेंद्र कुमार, सुदर्शन यादव, राजेश रंजन, नमनजय सिंह सहित सभी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

राजमणि चौधरी, रामकृपाल चौधरी, कमलेश कुमार चौधरी, मनो प्रताप चौधरी, राम शिवमणि चौधरी, राकेश चौधरी, सुजीत चौधरी, रामअम्बर चौधरी, मकरमदन वर्मा, कृष्णधर चौधरी, तिलकराम चौधरी, राम बहादुर चौधरी, गुलासा चौधरी, नीरज चौधरी, मनोज कुमार चौधरी, रामेश चौधरी, राम सुरेश चौधरी, वीरेंद्र वर्मा, रा. श्याम चौधरी, ज्ञानदास चौधरी, रामनाथ चौधरी, राकेश सिंह, अशोक वर्मा, आकाश चौधरी, कमलेश चौधरी, डा. राजकिशोर वर्मा, रामरक्षा वर्मा, डा. बालकेश चौधरी, शंशय पटेल, राजेश पटेल, जयेश्वर चौधरी, संजय चौधरी, जितेंद्र चौधरी, मनोज कुमार चौधरी, आशु चौधरी, अनन्त पटेल, सी.ए. चौधरी, महेंद्र चौधरी के साथ ही सरदार पटेल स्मारक संस्थान के अनेक पदाधिकारी, सदस्य एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल रहे।

जेल से रिहा होते ही आजम खान गिरफ्तार, ईडी ने कस्टडी में लिया

रामपुर (आभा)। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को ईडी ने रामपुर जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया है। बेटे अब्दुल्ला के साथ आजम जेल बाहर निकले। तभी ईडी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। दो बैंककाई मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत अर्जी मंजूर कर दी थी। हाईकोर्ट से जमानत के बाद आजम और अब्दुल्ला की ओर से एमपी-एमएलए सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट में अलग-अलग मामलों में जमानती दाखिल किए थे, जिनके सत्यापन के आदेश अदालत ने मुंबई और राज्य प्रशासन को दिए थे। पहले शुक्रवार को ही रिहाई की उम्मीद थी। लेकिन एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से आजम खान के विचारार्थ तीन पांच मुकदमों में रिहाई परवाने को रद्द कर दिए गए।

लेकिन, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिहाई परवाने जारी नहीं हो सके। जिसके चलते दोनों की रिहाई टल गई थी। लेकिन शनिवार को पूरी प्रक्रिया के बाद रामपुर जेल से आजम और अब्दुल्ला रिहा हो गए। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही आजम समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई थीं। लेकिन पाँचपाह का जेन शॉम होले-होले माफूसी में बदल गया था।

रामपुर जेल से बाहर आने पर

सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत को टुकड़ों में बटने से बचाया—ऐश्वर्य राज सिंह



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह के नेतृत्व में देश के पहले गुजराती भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल को जयन्ती पर याद किया गया। कृष्णानंद तट के निकट स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा कि भारतीय इतिहास में सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ आजादी के

समाजवादियों ने किया जयन्ती पर सरदार बल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेन्द्रदेव को नम्र

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शनिवार को लोह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल और महान समाजवादी चिंतक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य नरेन्द्र देव की 137वीं जयन्ती को उनकी जयन्ती पर याद किया गया। सरदार विधायक एवं सभा जिलाध्यक्ष महेंद्रनाथ यादव के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने पटेल जी के जीवन वृत्त, योगदान पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव आंकारनाथ पटेल ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की 562 रियासतों का विलय करके अखंड भारत के निर्माण के लिए जो योगदान दिया उसके लिये उन्हें नम्र याद किया जायेगा।

कहा कि आचार्य नरेन्द्रदेव शिक्षा के महान समाजवादी चिंतकों, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी, शिक्षा और समाजवादी विचारधारा के प्रसार- प्रसार के लिये समर्पित किया। उन्होंने समाजवादी आदर्श को जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सरदार विधायक एवं सभा जिलाध्यक्ष महेंद्रनाथ यादव ने कहा कि 1947 में भारत को आजादी तो मिली लेकिन विखरी हुई। देश में कुल 562 रियासतें थीं। अपनी कृतिनिष्ठता के बल पर पटेल ने इन्हें भारत में मिला लिया। इनमें पड़ोसी रियासत के नवाब ने 1947 में पालिसरत के साथ जमानत के फौज इंग्लैंड गये वह भी 36 साल की उम्र में। शुरुआत में दर से पड़ाई शुरू



आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नाम है। जिसकी सजा हमें दी जा रही है। हमें जेल में सजाया जा रहा है। जब मुश्किल से जमानत पर बाहर आते हैं, तो फिर से अंदर कर दिया जाता है। ईडी की टीम आजम खान को गाड़ी में बैठा कर ले आई है। इस दौरान आजम समर्थकों ने हंगामा किया।

बाद देश को एकजुट करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा। आजादी के समय देश में बिखरी 550 से अधिक रियासतों का भारत में विलय करके उन्होंने अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता और दृढ़ता का परिचय दिया। उनके प्रयासों ने भारत को टुकड़ों में बटने से बचाया और एक मजबूत, अखंड राष्ट्र की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई।

कहा कि सरदार पटेल ने कला था कि कठिन समय में कायर व्यक्ति बहाना ढूँढते हैं, बहादुर व्यक्ति बहादुर बन जाते हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयन्ती पर नम्र किया।

समाजवादियों ने किया जयन्ती पर सरदार बल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेन्द्रदेव को नम्र



—महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले युवा पीढ़ी—ओंकारनाथ पटेल

प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित किया। पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय, दयारंकर मिश्र, समीर चौधरी, मो. स्वालेह, राम सिंह यादव, मो. सलीम, अरविन्द यादव, रम बहादुर यादव, गुलाब सेनकर, राजेश यादव, हरेश्याम विश्वकर्मा, सलाउद्दीन, चन्दिना यादव, गगन पाण्डेय, रहमान सिद्दीकी, अखिलेश यादव, जावेद फिखरी आदि ने कहा कि आजकल जिस उम्र में बच्चे गैंगुएट हो जाते हैं उस उम्र में सरदार बल्लभ भाई पटेल ने 10वीं की परीक्षा पास की थी। उनकी शिक्षा ने उन्हें सच्चा ज्ञान और परिवार की आर्थिक गरीबी से आजाद किया। इसके बावजूद उन्होंने जिलाधिकारी की पदवी में सार्वजनिक अंग प्रकाश की। परीक्षा के सारा जमानत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गये वह भी 36 साल की उम्र में। शुरुआत में दर से पड़ाई शुरू करने वाले सरदार पटेल ने 36 महीने के वकालत के कोर्स को मजबूत 30 महीने में ही पूरा कर दिया। वे देश के महान नेता थे। वक्ताओं ने आचार्य नरेन्द्रदेव के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। लोह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेन्द्रदेव को नम्र करने वालों में मुख्य रूप से घनश्याम यादव, रम बहाल चौधरी, सुनील चौधरी, हिमांशु सिंह राठौ, मो. सज्जु, तुफानी यादव, अकिंत शुक्ला, अरविन्द सोनकर, युनुस आलम, नितान्त चौधरी, संदीप चौधरी, डब्ल्यू यादव, प्रमोद यादव, जितेंद्र यादव, पंकज यादव, राम स्वर्ण पास, मुहम्मद यादव, रायचंकर निराला, हनुमान चौधरी, विवेक यादव, मानसिंह यादव, इन्द्रजीत यादव, राविंद्र यादव, जयनंद यादव के साथ ही पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 1 नवम्बर 2026 रविवार

सम्पादकीय

नौकरी और चरित्र—प्रमाण पत्र

इसमें कोई दोषय नहीं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिसक नीतिविधियों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर सरकार हिसा की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से कोई पहल कर रही है, तो इसका आशय समझा जाना चाहिए। अगर सरकारें समांतर यह प्रश्न भी अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है कि हिसा को न चुनने देने के सरकार के कदम अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक स्वरों को बाधित तो नहीं करेंगे! गौरवलाह के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग-अलग विभागों और स्थानीय निकायों में सीबी मन्त्री से चुने जाने वाले अम्युथियों के चरित्र प्रमाणपत्र से जुड़े नियमों में एक अलग बदलाव किया है। इसके तहत यह कहा गया है कि राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से अगर कोई युवा सकल रूप से उत्तरकर हिसा करता है, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसे संगठन का सदस्य है, जिसका मकसद हिसा के जरिए समाज की व्यवस्था बदलना है, तो उसे भी अयोग्य माना जाएगा। हालांकि, यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा।

पिछले कुछ समय से दुनिया के कई देशों में सरकार के खिलाफ आम लोगों के प्रदर्शनों का जैसा स्वरूप देखा गया, उसमें जैसी हिसा और अराजकता देखी गई, उसे विवेक का लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहा जा सकता। ऐसे प्रदर्शनों से निपटना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। मगर यह जरूरी नहीं है कि भारत में भी सरकार से असहमति जाहिर करने के लिए ऐसे के युवा बलिदान करनी अपनाना। आमतौर पर हमारा देश लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखता है और इसी के अनुसार सरकार के समर्थन या विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राय अभिव्यक्त करता है।

ऐसे में हिसा के विरुद्ध किसी राज्य सरकार की ओर से अलग से नए नियमों की घोषणा की जरूरत का संदेह समझना मुश्किल है। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हिसा में स्पष्ट भागीदारी की अंतिम पुष्टि होने तक किसी को नौकरी के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में सरकार के नए नियमों की व्याख्या कौन करेगा। आम जनता के आंदोलनों में हिसा की परिभाषा किस आधार पर तय की जाएगी और यह कैसे सुनिश्चित होगा कि विरोध के किसी स्वरूप को सरकार 'हिसा' घोषित नहीं करेगी? यों यह कोई पहला मामला नहीं है कि हिसा के आधार पर नौकरी से वंचित करने का नियम लागू करने की कोशिश की जा रही है। वर्ष 2021 में बिहार में भी एक आदेश में कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हमला हुआ और उससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हुई, तो प्रदर्शन में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा।

तब इस संदर्भ में चरित्र प्रमाणपत्र निर्गत करने का भी निर्देश जारी हुआ था। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जारी नए नियमों का उद्देश्य वास्तव में विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले आम लोगों या युवाओं को हिसा से दूर रखना है या फिर इसके जरिए एक डर पैदा किया जाएगा, ताकि सरकार के खिलाफ असहमति के स्वर उभरने से पहले ही दब जायें?

जिस दौर में रोजगारी पकड़ने की देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में एक है, उसमें ऐसी शर्तों का वास्तविक असर क्या होगा? लोकतंत्र में हिसा की जगह नहीं हो सकती। मगर इसके लिए युवाओं को सरकारी नौकरी से वंचित रखने का नियम बनाना पड़े, तो क्या उसे अभिव्यक्ति पर अंकुश की तरह नहीं देखा जाएगा और क्या यह लोकतंत्र के जीवन को प्रभावित नहीं करेगा?

चक्रवात और आपदा प्रबंधन

भारत की खाड़ी से उपजे चक्रवात अनेक की जहाज से आगे से ज्यादा भारत में मौसम बिगड़ाना शुरू है। कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं बादल छाए हुए हैं, तो कहीं बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के करीब 14 राज्यों के लिए चेतावनी जारी कर रखी है। हालांकि, चक्रवात अर्न्त का सर्वाधिक असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सबसे ज्यादा होगा है। ओडिशा सरकार ने पूरी तैयारी दिखाई है, तो वहां किसी की भी जान नहीं गई है, जबकि आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में कम से कम पांच लोगों की मौत की दुख सूचना है। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान के प्रभावों की वजह से करीब 15,000 विजिलों के खम्बे उखाड़ गए हैं। वहां करीब 3,45 लाख किसान प्रभावित हुए हैं और 14 जिलों के 2,24,488 हेक्टेयर में खेती फसलें पानी में डूब गईं या खराब हो गई हैं। वैसे, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकारों की तालमेल होना चाहिए, इन्होंने समय रहते बचाव के इंतजाम किए हैं और हजाराों लोगों को खाली कराया है। वाकई, जान के नुकसान को कम से कम रखना सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

आंध्र में भारी बारिश के कारण अनेक जगह भूस्खलन हुआ है, सड़कें जलमग्न हुई हैं और पड़ उखड़ गए हैं। इसके बावजूद बाढ़ कोई हाताहत नहीं है। उत्तर कामगवाही से सीखने की जरूरत है। जिस तरह बड़े जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे तूफानों या चक्रवातों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी आमजनका बढ़ती जा रही है। ऐसे में, हमारे पास सावधाना और तैयार रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नीति के तहत पहले जहाजनों को बचाना और उसके बाद अन्य प्रकार के नुकसानों को रोकने के पुष्का इंतजाम होने चाहिए। यह भी एक बड़ी धिता की बात है कि ऐसे चक्रवात आमतौर पर अप्रैल-मई में देखे जाते हैं। यथा मौसम के साथ आपदाओं का चक्र भी बदल रहा है? आपदाएं पहले की तुलना में ज्यादा घातक हो रही हैं? हम यह देख पा रहे हैं कि भारत ही नहीं, बिकसित देशों को भी आपदाओं का सामना करने में अब बहुत चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। ध्यान रहे, पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे समुद्री जल गर्म हो रहा है और वहां से उठने वाले आपदाओं की तीव्रता बढ़ रही है। यह अल नीनो वर्ष है और इसके दौरान महासागरों में बेसिन में उप-कण्टीनैय चक्रवात कम बार आते हैं और उनकी तीव्रता भी कम होती है। लेकिन चक्रवात अर्न्त ने इस आकलन को धावा बोल दिया है।

सानल रहे, अल नीनो वर्ष में भारी वर्षा, तूफान, चक्रवात, आगजनी, बाढ़ इत्यादि का खतरा ज्यादा मंडराएगा। संतोष की बात है कि हम इसके लिए बहुत दूर तक तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसी आपदाओं के समय कई सरकारों का राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर मुमकिन प्रबंध करने चाहिए और ऐसे प्रबंधों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सरकारी बाज में है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल व राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को समय रहते तैनात किया गया और प्रभावित राज्यों में बचाव व राहत अभियान युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। नुकसान का यथोचित आकलन करके मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार मृतकों के परिवजन को पांच-पांच लाख रुपये दे रही है, लेकिन उसे अभ्यजन करना चाहिए, चेतावनी के बावजूद पांचों लोगों की मौत कैसे हुई? बचाव के इंतजाम कैसे अहुरे रह गए? आपदा प्रबंधन में दिखी कमियों को महसूस से बचना होगा।

अखिलेश के पीडीए के खिलाफ शाह का यूसीसी दांव



—संजय सक्सेना—

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी दलित-पिछड़ा-अल्पसंख्यक की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता का मुद्दा लेकर आ गई है। इस बात का संकेत गुजर मंत्री अमित शाह ने लखनऊ दौरे के दौरान दिया। शाह ने दो दूक कहा कि उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव केवल सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि वैचारिक मुद्दों, सामाजिक समीकरणों और विकास के दावों का बड़ा मुकाबला बनेगा। शाह ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार बनते ही प्रदेश में सामान नागरिक संहिता (यूपीसी) लागू कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि शाह यूसीसी के संकेत यूपी में चुनौती बहस का रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे हमले करके उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि अब चुनौती तैयारी में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि शाह के यूसीसी



लागू करने वाले बयान के पीछे एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा छिपा है। सवाल यह भी है कि क्या भाजपा अपनी उपलब्धियों के भरपूर तीसरी बार सत्ता में लौटना चाहती है या 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके ने उसे संप्रति से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है? बहरहाल, सपा के पीडीए के खिलाफ शाह का यूसीसी का एलान भाजपा की चुनावी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। यूसीसी के सहारे भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करेगी, वहीं सपा में चुनौती बहस का रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे हमले करके उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि अब चुनौती तैयारी में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि शाह के यूसीसी

दरअसल, उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू करने का वादा करके भाजपा ने अपने पुराने वैचारिक एजेंडे को फिर चुनाव के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ शाह यूसीसी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शाह 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। 2017 में भाजपा ने 403 में से 312 सीटें हासिल की थीं और करीब 39.67 प्रतिशत वोट पाए थे। 2022 में पार्टी की सीटें घटकर 255 रह गईं, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़कर 41.29 हो गया। इन आंकड़ों से भाजपा की मजबूत चुनावी स्थिति जरूर दिखाई देती है, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस आत्मविश्वास को चुनौती दी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 37 और भाजपा ने 33 सीटें जीतीं। कांग्रेस को छह सीटें मिलीं। यह नतीजा बताता है कि भाजपा के

सामने विपक्ष की चुनौती वास्तविक है। सपा ने सामाजिक समीकरणों और गठबंधन की राजनीति के सहारे अपनी ताकत बढ़ाई है। इसीलिए शाह का कार्यकर्ताओं से आपसी भावनाओं मुलाकर मतदान में उत्तरने का आग्रह महत्वपूर्ण है। शायद समय रहते शाह को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का अहसास हो गया है। उनका चुनाव से पहले संगठन की एकजुटता पर इतना जोर देना बताता है कि पार्टी बूथ स्तर पर किसी भी कमजोरी को नजरअदाज नहीं करना चाहती। टिकट की दवावेदार, स्थानीय नेताओं की खींचतान और जातीय समीकरण भाजपा के लिए बड़े चुनौती बन सकते हैं। 2024 ने दिखाया कि बड़े नेताओं की लोकप्रियता के बावजूद स्थानीय अस्तंतेर चुनावी परिणाम बदल सकता है। भाजपा को अब कलम पुराने चुनावी आंकड़ों पर निर्भर रहने के

बजाय जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी।

योगी सरकार को कानून-व्यवस्था को शाह ने चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपराध में कमी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। सरकार की उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2016 की तुलना में उर्कती के मामलों में करीब 90 प्रतिशत और लूट में 84 प्रतिशत की गिरावट आई है। लेकिन कानून-व्यवस्था का मूल्यकन केवल अपराध के प्रतिशत से नहीं हो सकता। महिलाओं की सुरक्षा, आम नागरिक की धाने में सुनवाई और अदालतों में न्याय मिलने की प्रक्रिया भी उरनी ही जरूरी है। बुलडोजर कार्रवाई राजनीतिक संकेत दे सकती है, लेकिन कानून का राज निष्ठा जांच और संवेधानिक प्रक्रिया से ही स्थापित होता है। निवेश के मोर्चे पर भी शाह ने 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों और 15 लाख करोड़ रुपये के जमीन पर उत्तरने का दावा किया। यह प्रदेश की अव्यवस्था के लिए बड़ी संभावना है, लेकिन जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल रोजगार का है। कितनी परियोजनाएं वास्तव में शुरू हुईं और उससे कितने युवाओं को नौकरी मिली? निवेश सम्मेलन में हुए समझौते तभी निशान हैं, जब वे उद्योग, उत्तर प्रदेश और रोजगार में बदलें। उत्तर प्रदेश का युवा आज भी बेहतर अवसरों के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करता है। सरकार को यह साबित करना होगा कि निवेश के बड़े दावे आम परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव ला रख पाएगा।

इसके साथ ही शाह ने वोटर्स को लुभाने के लिए गरीबी के सवाल पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। नीति आयोग के जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 2013-14 से 2022-23 के बीच देश में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। उत्तर प्रदेश में यह संख्या करीब 5.94 करोड़ बढ़ाई गई। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन हकीकत यह भी है कि गरीबी से बाहर निकलने और स्थायी आर्थिक सुखहासिल करना दो अलग बातें हैं। महंगाई, किसानों की आय, बेरोजगारी और छोटे कारोबारियों की समस्याएं अभी भी चुनावी बहस का हिस्सा रहेगी। इन खयालों का जवाब केवल आंकड़ों से नहीं, जमीन पर दिखाई देने वाले बदलावों से देना होगा। लम्बोउपवास यह है कि भाजपा 2027 की लड़ाई में यूपीसी, कानून-व्यवस्था और विकास को एक साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन सत्ता की तीसरी पार्टी का रास्ता केवल नागरिक और राजनीतिक हमलों से नहीं निकलेगा। अंगद के पांव की तरह सरकार अडिग होने को दावा करने वाले शाह को भी पता है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है। भाजपा के मामले में असली चुनौती यही है कि वह अपने वादों को जमीन पर उतारे और रोजगार, शिक्षा, किसानों खास सामाजिक न्याय जैसे सवालों का ठोस जवाब दे। 2027 में चुनावी विसात पर घाली सत्त बनेंगे, लेकिन जिन चीतों की होगी जो जनता का भारोसा कायम रख पाएगा।

चक्रवातों के साजे में तटीय भारत का भविष्य



—डॉ. प्रियंका सौरभ—

समुद्र जितना जीवनदायी है, उसका रूढ़ रूप उतना ही विनाशकारी हो सकता है। भारत की करीब 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए बेहतर अहम है। लेकिन यही तटीय क्षेत्र हर साल चक्रवातों, समुद्री सुफानों, बाढ़ और तटीय कटाव का खतरा भी झेलते हैं। चक्रवात अर्न्त ने एक बार फिर तटीय भारत की संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन की तैयारी पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल केवल यह नहीं है कि चक्रवात कब और कहाँ आएंगे, बल्कि यह भी है कि उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। बदलते मौसम के दौर में अब आपदाओं को रोकने के बाद राहत पहुंचाने के बजाय पहले से नुकसान कम करने की रणनीति बनानी होगी।

चक्रवातों से निपटने में सबसे बड़ी चुनौती उनके बदलते स्वरूप और तीव्रता का अनुमान लगाना है। आधुनिक तकनीक और मौसम पूर्वानुमान में सुधार के बावजूद कई बार चक्रवात कम समय में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन के पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री जुटाने के लिए बहुत कम समय बरता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, सूदृढ़ में उठने वाली ऊंची लहरें और भूस्तरों में बाढ़ एक साथ तबाही मचा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है।

तटीय क्षेत्रों में कमजोर बुनियादी ढांचा भी बड़ी समस्या है। चक्रवात के दौरान बिजली के खंभे गिर जाते हैं, सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और संभर संपाद उप पड़ जाती हैं। इससे राहत और बचाव कार्य प्रभावित होते हैं। कई तटीय शहरों में अनियोजित निर्माण, जल निकासी की खराब व्यवस्था और निवेश इलाकों में बस्तियों का विस्तार इलाकों को बड़ा रहा है। ऐसे में आपदा के समय लोगों को बचाने के साथ-साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल



चक्रवात का असर सभी पर समान नहीं पड़ता। गरीब परिवार, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जिन परिवारों की आजीविका खेती, मछली पकड़ने या रिहाई मजदूरी पर निर्भर है, उनके लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना भी आसान नहीं होता। उन्हें अपनी संपत्ति, पशुओं और रोजगार की धिता सताती है। चक्रवात के बाद मछली पकड़ने का काम बंद हो जाता है, खेतों में खारा पानी जाता है और छोटे कारोबार ठप पड़ जाते हैं। इससे प्रभावित परिवारों के सामने लंबे समय तक आर्थिक संकट बना रहता है।

करना भी बड़ी चुनौती बन जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की पूर्व चेतावनी प्रणाली पहले से बेहतर हुई है, लेकिन चुनौती अब भी यह है कि चेतावनी समग्र पर हर व्यक्ति तक पहुंचे। समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों, दूरदराज के गांवों और छोटे द्वीपों में रहने वाले लोगों तक सूचना पहुंचाना आसान नहीं है। कई बार लोग चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते या घर और आजीविका छोड़ने के डर से सुरक्षित स्थानों पर जाने में देरी करते हैं। इसलिए केवल चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को उसके खतरों और उससे बचने के उपायों के बारे में समझाना भी जरूरी है।

चक्रवात का असर सभी पर समान नहीं पड़ता। गरीब परिवार, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जिन परिवारों की आजीविका खेती, मछली पकड़ने या रिहाई मजदूरी पर निर्भर है, उनके लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना भी आसान नहीं होता। उन्हें अपनी संपत्ति, पशुओं और रोजगार की धिता सताती है। चक्रवात के बाद मछली पकड़ने का काम बंद हो जाता है, खेतों में खारा पानी जाता है और छोटे कारोबार ठप पड़ जाते हैं। इससे प्रभावित परिवारों के सामने लंबे समय तक आर्थिक संकट बना रहता है।

प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कमजोर होना भी धिता का विषय है। मौसम के कटाई, आर्द्रमृगों का विनाश और समुद्र तटों पर बढ़ता निर्माण चक्रवातों के खतरों को बढ़ाते हैं। मौसम बन समुद्री लहरों की ताकत कम करने और तटीय इलाकों को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की मौत पर होने वाला विकास मध्य के लिए बड़ा संकट बन सकता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहले पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना होगा। मौसम विभाग की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के साथ उपग्रहों, डॉक्टर रडार और समुद्री निगरानी तंत्र का विस्तार करना होगा। चेतावनी केवल मोबाइल संरंशों तक सीमित न रहे। मौसम, सामुदायिक रेडियो, स्थानीय प्रशासन और पंचायतों के माध्यम से भी सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए। चेतावनी प्रणाली भाषा में हो और उसमें यह उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब जरूरत राहत और बचाव तक सीमित रहने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनने की है जो आपदा से पहले ही नुकसान को कम कर सके। आधुनिक, सुरक्षित घर केवल मजबूत इमारतों से नहीं बने, बल्कि जागरूक नागरिकों, जवाबदेह प्रशासन और संक्षिप्त तैयारीयन से बनते हैं।

इसके साथ ही तटीय इलाकों में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। कच्चावत आभ्यर्थलों की संख्या बढ़ाने, सुरक्षित निकासी मार्ग बनाने और अस्पतालों, बिजलीघरों, सुरक्षित घर केवल मजबूत इमारतों से नहीं बने, बल्कि जागरूक नागरिकों, जवाबदेह प्रशासन और संक्षिप्त तैयारीयन से बनते हैं।

कई सवाल छोड़ गया एमएलसी चुनाव!



— दीपक कुमार त्यागी—

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वापसनी, खासगी राजनाथ सिंह की सीट लखनऊ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ नागपुर के एमएलसी सीटों के इन चुनाव परिणामों के बाद अब पार्टी में ही संगठन की राजनीति और प्रत्याशी चयन पर सवाल उठने की गुप्तसु सुनाइयाहट शुरू हो गई है। देश के चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक) की 28 विधान परिषद (एमएलसी) सीटें पर चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, सभी राजनीतिक दल व विलसक परिणामों का अध्ययन करके अपने अपने लाल-हानि के हिसाब से अपने निष्कार रहे हैं। लेकिन इस बार का यह चुनाव कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जिनका जवाब राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों के साथ विश्लेषक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को देखे जा सकते हैं। क्योंकि भाजपा को अन्य दलों से अलग मानते हुए किसी व्यक्ति या परिवार की जागीर की जगह संगठन को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल माना जाता है और वैसे भी अनुरूपी ट्यूबवाली से दूर अनुशासन वाली पार्टी मानने का दावा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमेशा सामाजिक रूप में किया जाता है। लेकिन एमएलसी के चुनावों में पड़ते हैं और पार करे तो उत्तर प्रदेश की हॉट सीट वाराणसी, लखनऊ व महाराष्ट्र में नागपुर जैसी हार्डकोरफ़ल सीट पर हारने के पीछे भाजपा के कुछ राजनैतियों की भी महत्वकांक्षा व अनुशासन का तार-तार होना बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है। पहले पार्टी के अधिकार संगठनांत व कार्यकर्ता निर्यात वर से कांय करते हुए धरतार पर नजर आते थे, लेकिन लंबे समय से सत्ता का सुख लगातार भाजपा के कारण अब पार्टी के कुछ राजनैतियों का अहंकार अपने घरम में और यह सत्ता के बंद में बूर होकर के जिताने को ठेगा दिखाकर चित्तात हुए पार्टी के केंद्रीय व प्रशं नेतृत्व को भी दिश-निर्देशों की आये दिन अनदेखी करने का कार्य कर रहे हैं।

जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह के दौर की भारतीय जनता पार्टी की पहचान एक ऐसे राजनीतिक दल के रूप में होती है, जिसके कार्यकर्ता व नेता किसी भी तरह के चुनावों को हर्कते में नहीं लेते हैं। लेकिन जितन तरह से उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन रहा है, उसने तो पार्टी के रणनीतिकारों को जीती हुई व हारी हुई सभी ही सीटों के परिणाम पर विस्तार से विश्लेषण करने के लिए सारे पर मजबूर कर ही दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को योगी सरकार के कार्यों के दम पर चुनावों में जीत की हिसाब से अपने निष्कार रहे हैं। जिस वजह से पार्टी के विधानसभा चुनाव सर पर इस वजह में पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार एमएलसी चुनावों की जीत सार पर भाजपा प्रत्याशी की हार का और बदकार के विश्वासी होने के जनता की अदवास्त से पर उदासकर के भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया चाहते थे। लेकिन सूत्रों के अनुसार लगातार मीटिंग व इंडिंग के बाद भी कुछ भाजपा नेताओं की ही कीटिंग के बलते भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का यह बड़ जग अदवास्त में उलटा हो गया है, जिसका खासिगाम भारतीय जनता पार्टी को एमएलसी चुनावों की रणनीति में कुछ सीटों पर हार के रूप में उठाना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी, खासगी राजनाथ सिंह की सीट लखनऊ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ नागपुर के एमएलसी सीटों के इन चुनाव परिणामों के बाद अब पार्टी में ही संगठन की रणनीति और प्रत्याशी चयन पर सवाल उठने की गुप्तसु सुनाइयाहट शुरू हो गई है। अही कुछ राजनैतिक विश्लेषकों की मानें तो हार्डकोरफ़ल सीटों के असा-बल वाराही सीटों पर भी जीत का और भाजपा के कुछ अग्रणी ही लोगों का भीतरबल, दवावेरों व अन्य जिम्मेदार लोगों को द्वारा सभी दल से मोट भी बनवाने प्रत्याशी चयन पर सवाल, संगठन के द्वारा बनाई गई जीत की रणनीति और कुछ अपनों के ही द्वारा चुनाव में की योगी कीटिंग की खील-खीलकर के स्वयं ही पीत खीलने का कार्य रही है।

सरदार पटेल की जयंती मनाई गई, कार्यक्रम में वक्ताओं ने देश की एकता में उनके योगदान को याद किया



संसारदा वल्लभाभिः पदलैः के आदर्श को अंगीकार करते हुए अधिवक्ताओं के उद्घोषण के विरोध में तथा आवक्ताओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिवक्ताओं को अपना सर्वोच्च निष्कार करने का आवाहन किया है। बाइक रन के बाद अधिवक्ताओं ने आम सभा की बैठक की। बाइक रन की आगमना में पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह, मैट्रु त्रिपाठी, अनूप सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, वकील प्रसन्नदास, वशिष्ठ सिंह संतोष पटेल, सुप्रसन्न सिंह गांधी, महताप अमजितीय सिंह, जगमोहन आशीष प्रसाद, दिग्विजय भूडे, हर्दय मिश्रा, केशव अग्रिमहोत्री, कोराल कुशुभा पांडे, दयानाथ चौहरी, आशीष शिरोर, मंडे पांडेय, निरिजेश मिश्रा, अरुण सिंह सहित बहुत सँख्या में अधिवक्ताओं अपनी सहभागिता सुनिश्चित की।

अध्यापन और कल्याणकारी कार्य करता था। उन्होंने देश को एक सूत्र में गिरोने के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किया, वह आज वाली पीढ़ीसे के लिए सरव प्रेरणादायक बना रहेगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से सरदार पटेल के विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में आसपास करने की अपील की। वक्तोक्ति ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में आपसी भाईचारे, एकता और राष्ट्रप्रेम की भावना को प्रकट करना चाहिए। इस दौरान चंद्र प्रकाश तिवारी, समीप राव, वीरेंद्र प्रताप शाही, नमजरा तिवारी, नंदा पंडेय, संजय मिश्रा, जयनाराय प्रसाद, नंदी हनुन, नम्रता तिवारी, अमित शर्मा और सौरभ चौहान

निवाह भेता मिलगा। राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

16 से शुरू होगी स्व-गणना, हर गांव में बनेगी हेल्प डेस्क

संवाददाता-महाराजगंज।

जनगणना-2027 के दूसरे चरण के



से 30 नवंबर तक चलने वाले जनगणना में हर दिन एक हीयम बनाया गया है। इसमें पहले दिन सेवक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एमपी, एमएलए, एमएलसी, दूसरे दिन लोकल गवर्नमेंट व क्लरक डेवेलपमेंट से खुदे लोगों को स्वागताना में हर दिन प्रेस विलोगा जाएगा। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, उद्योग, बाजार और

लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के

आधार पर करें निस्तारण —डीएएम

संबाददाता-श्रावस्ती। जिसलिए जारी अनुमतिपत्रों की कक्षाओं में शनिवार को कलेक्टर ने समाचार में समाज कल्याण, अंतरसंस्था कल्याण, सहायक कल्याण, दिव्यांग जन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संकेतित योजनाओं की प्रगति निरीक्षण के लिए आदेशित की।

कलेक्टर ने लिए आदेशित करने का कहा जिसमें समाज कल्याण योजनाओं की की सीमाएं कलेक्टर हुए उपस्थित दिशावली में को आदेशित कल्याण विभाग के लिए संकेतित वृत्तों तथा उनके अधिकार का संस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। महिला कल्याण विभाग पर निरीक्षण निरीक्षण और सुलभता

१५ वरक मे योजनेअओ क
किमान्यन, लवित आवेअओ और प्रा
समाधायिओ को हुल रेह लाम की
समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने
सभी लवित प्रकरणों का प्राथमिकत
के आधार पर शीघ्र निस्तारण कर
के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग
की समीक्षा में धृष्टवृत्ति, मुख्यमंत्री
सामूहिक विहाय योजना, शहीद अनुदान
वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री अनुसुदर
योजना तथा अल्पचारा निवारण अ
निमेष से संबंधित योजनाओं की प्रगति
जानी। उन्होंने लवित आवेअओ और
आकर जोड़ने के कार्य को शीघ्र पूर
करण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री विधायक योजना के तहत
अधिकारियों को कम्प्यूटर का माहिर बन

सरदार पटेल की जयंती धूम धाम से मनाई गई

के विजय पर माना बढ़ाई और दीक्षा जलया। काषाय्यक विना तिवारी, प्रवेक ईजीनियर आकारा तिवारी, प्रवेक ईजीनियर प्रकृति तिवारी और शिक्षक-शिक्षिकाएं भी मौजूद रहे। प्रवेक निदेशक ने छात्रों को बताया कि पढ़ेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में किसान परिवार में हुआ था। उनके

पिता का नाम धुवेरावजी और माँ का नाम लालबाई था। उन्होंने बाल्य में पढे स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी के बाद भारत के पहले उच्च प्रमाणन की ओर गृह मंत्री बने। उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की डिग्री की और अहमदाबाद में बकायत शुरू की महान्या गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए पटेल की जयंती को पटेल में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी दुर्घटना के कारण उन्हें भारत का लौक पुरस्कार का जाता है। कार्यक्रम में आद्य तपस्वियों साक्षी शुक्ला और गरिमा चौधरी पटेल के जीवन पर भाषण दिए श्रीमती, बालिया, सिमर, अनुजोति उमजि, अंशिका, यामिनी, रूचा जी अतिथियों ने कला का प्रदर्शन किया

द्वेद न समोद्गायित्वा विवर्तयति। अत्र
आज ध्वनेन के साथ पिशा और
सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में योगदान
। उन्होंने कहा कि उनके विचारों में
आज भी समाज को दिशा देते हैं।
अनुष्ठान नहीं कहा कि महापुरुषों की
संस्था, विचार और आदर्श नहीं मीट
कल पड़वाना समाज की जिम्मेदारी है
उनके बाद एएस आरसी के भाई
में समाप्त, एकता और भाईचारे का
हमना मजबूत की जा सकती है।
इस मौके पर रावकुमार वारी ने
आचार्य रमेश देव के व्यक्तिगत और
काम के बारे में बताया। कार्यक्रम में
संस्थान सिंह, जयधन सहनी, श्रद्धांत
साहनी, सचिन रावत, राजेश शर्मा,
ज्ञानेश्वर सिंह, अनुर हरिजन,
कमलेश सिंह, अशोक जयसवाल,
मिंदू भाषाया, ध्यान भाषा, समीर
माती, उमेश सिंह और श्रीराम चौहान
सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

के अनुसार, योजना का तहत हर जोड़े पर कुल एक लाख रुपये खर्च किए गए। इसमें 68 हजार रुपये विवाहित के खাতে में होते जाते हैं और 21 हजार रुपये की गुरुष्णी की सामग्री दी जाती है। बाकी 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च होते हैं। योजना का लाभ सभी वर्गों के उन गरीब परिवारों को दिया जाता है, जिनकी सालाना आय कम से कम लाख रुपये तक है। कार्यक्रम में बीडीओ, स्तोत्राचम, कुपुआ, द्वाकै, मुमुक्षु सुमति शाही, परचुरलकुल प्रेसिडेंट प्रमुख सामग्री गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष जयवंत कुपुवावा, पंचायती प्रसाद, रवींद्र शर्मा कुपुवावा, मंडल अध्यक्ष रविश शाही, संजय सिंह, प्रमोद दास, विक्रम राय, रंजन भीरावराव, जीवन पति निपाटी और मनोज भारती सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

